आर.एन.आई. पंजीयन क्र. 39596/82 ( डाक पंजीयन MP/IDC/1462/2016-2019 )

साप्ताहिक

# मालव अँचल

वर्ष 47 अंक 42 (प्रति रविवार) इंदौर, 07 जुलाई से 13 जुलाई 2024 पृष्ठ-8 मूल्य 3 रुपये

## इंडिया गठबंधन, लोको पायलट के कामकाजी हालात में सुधार के लिए संसद में आवाज उठाएगा

**नई दिल्ली।** लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रविवार को लोको पायलट से जुड़े मुद्दों को उठाते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन उनके अधिकारों और कामकाजी परिस्थितियों में सुधार के लिए संसद में आवाज उठाएगा। राहुल गांधी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लोको पायलट के साथ अपनी हालिया बातचीत का एक वीडियो एक्स पर पोस्ट कर यह टिप्पणी की। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा, नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में लोको पायलट की जिंदगी की गाड़ी पूरी तरह से पटरी से उतर गई है। उन्होंने कहा कि लोको पायलट को गर्मी से खौलते केबिन में बैठकर 16-16 घंटे काम करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।

राहुल गांधी ने एक पोस्ट में कहा, जिनके भरोसे करोड़ों जिंदगियां चलती हैं, उनकी अपनी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। यूरिनल (मूत्रालय) जैसी बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित लोको पायलट के न काम के घंटों की कोई सीमा है और न ही उन्हें छुट्टी मिलती है। इस कारण वे शारीरिक और मानसिक रूप से टूटकर बीमार हो रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि ऐसे हालात में लोको पायलट से ट्रेन चलवाना उनकी और यात्रियों की जान को जोखिम में डालना है। राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया

गठबंधन लोको पायलट के अधिकारों और कामकाजी हालात को बेहतर किए जाने के लिए संसद में आवाज उठाएगा।

बातचीत का वीडियो साझा करने के साथ राहुल गांधी ने कहा, इस छोटी सी चर्चा को देखकर आप भी उनकी पीड़ा को महसूस कर सकते हैं। वीडियो में लोको पायलट ने राहुल गांधी से आराम की कमी, छुट्टी न मिलने और अमानवीय कार्य स्थितियों की शिकायत की है। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के दक्षिण जोन अध्यक्ष ने शनिवार को लोको पायलट को लेकर गांधी को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें हालिया रेल दुर्घटनाओं के लिए खराब कामकाजी परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहराया गया। आर. कुमारेसन ने शुक्रवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर गांधी और लोको पायलट के बीच बातचीत के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

कुमारेसन ने न्यूज एजेंसी को बताया कि वे रेलवे में लोको पायलट और यात्रियों के सामने आने वाले गंभीर सुरक्षा मुद्दों की ओर राहुल गांधी का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे। ट्रेन चालक संघों ने रेलवे के इस दावे का भी खंडन किया है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उन लोको पायलट से मुलाकात की, जो दिल्ली मंडल से नहीं थे, बल्कि बाहर से लाये गये थे।

राहुल गांधी ने शुक्रवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लोको पायलटों से मुलाकात की थी, जिसके बाद उत्तर रेलवे (एनआर) के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि राहुल गांधी ने जिन लोको पायलट से मुलाकात की, वे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की क्रू लॉबी (लोको पायलट के लिए निर्धारित स्थल) से नहीं थे। दिल्ली मंडल उत्तर रेलवे के अंतर्गत आता है। राहुल गांधी ने लोको पायलट से बात करके उनकी समस्याओं और चुनौतियों के बारे में जानकारी हासिल की थी। राहुल गांधी ने उन्हें आश्वासन दिया था कि वह संसद में उनके मुद्दे उठाएंगे। पार्टी सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर देशभर से आए करीब 50 लोको पायलट से मुलाकात की और उन्होंने उन्हें अपनी समस्याएं बताईं।

## आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोज्य योजना में बड़े बदलाव की तैयारी

### 5 नहीं अब 10 लाख हो सकता है बीमा कवर!

**नई दिल्ली।** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार इसी महीने पूर्ण बजट पेश करने वाली है। इस बार देश में गठबंधन की सरकार बनी है, तो लोगों को इसके लोकलुभावन होने की उम्मीद है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार इस बजट में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत योजना को लेकर कुछ बड़े ऐलान किए जा सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र आयुष्मान भारत योजना के तहत कवरेज लिमिट को 5 लाख से बढ़ाने पर विचार कर रहा है। एनडीए सरकार आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोज्य योजना के लाभार्थियों की संख्या और बीमा राशि दोनों को बढ़ाने पर विचार कर रही है। इसमें सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि योजना के तहत लाभार्थियों को मिलने वाली कवरेज लिमिट को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये प्रति वर्ष करने की तैयारी है। रिपोर्ट की मानें को एनडीए सरकार अगले तीन सालों में अपनी प्रमुख आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लाभार्थी आधार को दोगुना करने पर विचार कर रही है। अगर सरकार अगले तीन साल में आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोज्य योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या को बढ़ाकर दोगुना करने का ऐलान करती है, तो फिर देश की दो-तिहाई से ज्यादा आबादी को स्वास्थ्य कवर मिल सकेगा। रिपोर्ट में सूत्रों ने कहा है कि सरकार इस मामले में इसलिए विचार कर रही है, क्योंकि इलाज पर होने वाला भारी भरकम खर्च परिवारों को कर्ज के जाल में धकेलने वाले सबसे बड़े कारणों में से एक है। उन्होंने कहा कि इसके मद्देनजर सरकार आयुष्मान योजना की कवरेज राशि की लिमिट को मौजूदा 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने के प्रस्ताव को अंतिम रूप देने पर भी विचार-विमर्श कर रही है।

## सांसद महुआ मोइत्रा नए मामले में फंसी

**नई दिल्ली।** टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा अभी कैश फॉर क्वैरी मामले से उबर भी नहीं पाई कि एक और नए मामले ने उन्हें जकड़ लिया है। अभद्र टिप्पणी मामले में उन्हें आरोपी बनाते हुए पुलिस की साइबर यूनिट ने एफआईआर दर्ज की है। एक बार फिर सांसद महुवा मोइत्रा विवादों के बीच अभद्र टिप्पणी को लेकर नए मामले में फंसती दिखी हैं। सांसद मोइत्रा के खिलाफ दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की साइबर यूनिट द्वारा एफआईआर दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि उनके खिलाफ बीएनएस की धारा 79 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। यहां बतलाते चलें कि सांसद महुआ मोइत्रा द्वारा सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफार्म में की गई पोस्ट में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगा है। इस मामले को लेकर महिला आयोग शुक्रवार को दिल्ली पुलिस में शिकायत करने पहुंचा था। सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोपी बनाते हुए सांसद मोइत्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। इससे उनके लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है।

## हैकर्स का बड़ा अटैक! 995 करोड़ पासवर्ड लीक : रिपोर्ट में हुआ खुलासा

**नई दिल्ली।** साइबर सुरक्षा का खतरा दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। अक्सर खबर आती है कि किसी कंपनी का डेटा लीक हो गया। ऐसे में एक हैरान करने वाली जानकारी सामने आई है कि अब तक का सबसे बड़ा डेटा लीक हुआ है। लगभग 995 करोड़ पासवर्ड लीक हो गए हैं। शोधकर्ताओं के मुताबिक, यह पासवर्ड लीक अब तक का सबसे बड़ा लीक है।

**रिपोर्ट में चौंकाने वाली जानकारी**-फोर्ब्स के मुताबिक, ObamaCare नाम के हैकर ने 995 करोड़ पासवर्ड लीक कर दिए हैं। यह जानकारी गुरुवार को Rockyou2024 रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि Rockyou2024 के मुताबिक, दुनियाभर में सिंगल स्तर पर इस्तेमाल होने वाले पासवर्ड लीक हुए हैं। रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि जो पासवर्ड लीक हुए हैं, उनमें से कई अभिनेताओं की डिटेल भी शामिल है।

**लॉगइन जानकारी भी हुई है लीक**-साइबरन्यूज के मुताबिक, Rockyou2024 ने बताया है कि कई अभिनेताओं का पासवर्ड कई ऑनलाइन अकाउंट पर अवैध एक्सेस लेने के बाद हासिल किया है। इसमें कई कर्मचारियों का डेटा भी लीक हुआ है। शोधकर्ताओं के मुताबिक, कई पासवर्ड पुराने और नए डेटा लीक की मदद से यह जानकारी हासिल की गई है। इस मिले-जुले डेटा लीक के साथ ही ईमेल एड्रेस और कई लॉगइन जानकारी भी लीक हुई है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि Rockyou2024 ही व्यक्तियों की पहचान चुराने और आर्थिक अपराध के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। मगर ऐसा पहली बार हुआ है कि Rockyou2024 का हाथ पासवर्ड लीक में आया है। रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि इससे पहले हैकर्स ने 8.4 बिलियन प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड लीक किए हैं।

**साइबर सुरक्षा को लेकर कदम**-वहीं, साइबर सुरक्षा के लिए कई सारे काम किए जा रहे हैं। यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों से यह पूछा है कि साइबर हाइजिन के लिए क्या-क्या कदम उठाए हैं। यूजीसी ने साइबर हाइजिन के मसले पर वेबिनार में यह जानकारी मांग थी। उधर, गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के मुताबिक, सभी साइबर अपराधों में छात्रों को बचाने के लिए समूह के स्तर पर जागरुकता अभियान का अधिक से अधिक प्रचार करना है।

# संपादकीय

## सीवर लाइन के बावजूद सभी बड़े शहरों में जल प्लावन की स्थिति

भारत के सभी बड़े शहरों में स्वच्छता अभियान के तहत सीवर लाइनों का काम पिछले कई वर्षों से किया जा रहा है। सरकार ने इसमें अरबों रुपए खर्च किए हैं। महानगरों से लेकर ए और बी क्लास के सभी शहरों में सीवर लाइन का काम पिछले दो दशक में बड़ी तेजी के साथ हुआ है। नालियों को सीवर लाइन से जोड़ा गया है। सारे शहर का पानी सीवर लाइन के माध्यम से ट्रीटमेंट करके बहाने की व्यवस्था की गई है। दूसरी तरफ हकीकत यह है कि शहर के जो भी नाले थे उन पर भारी अतिक्रमण हो गया है। हर शहर में जो खुली जमीन पड़ी हुई थी उसमें बड़े-बड़े भवन बना दिए गए हैं। अब जब बारिश होती है और खासकर थोड़ी सी बारिश में ही शहरों के अनेक हिस्सों में पानी भर जाता है। निचली बस्तियों में नाव चलाने की नौबत आ जाती है। पूरा जनजीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि शहरी विकास में पुरानी संरचना और नई संरचना को जोड़ने में जिस तरह के कार्य किए जाने थे वह नहीं किए गए। हर शहर में करोड़ों रुपए की सीवर लाइन के ठेके हुए। सीवर लाइन बनाते समय यह ध्यान नहीं रखा गया कि पानी का ढलान जहां से सीवर लाइन शुरू हो रही है और जहां पर जाकर वह मिलेगी उसके बीच में ढलान है या नहीं। सीवर लाइन बनाने और ठेके में भारी भ्रष्टाचार के चलते केवल बड़ी-बड़ी नालियों को सीवर लाइन दी गई, उनके अंदर सीवर लाइन के पाइप डाल दिए गए। कंक्रीट के जरिए एक नाला बना दिया गया। लेकिन जैसे ही बरसात आती है वह पानी इन सीवर लाइनों और नालों से बहकर शहर के बाहर नहीं निकल पाता है। जिसके कारण जल प्लावन की स्थिति हर साल बनती है। इसमें करोडों-अरबों रुपए का नुकसान नगरीय संस्थाओं और सरकारों के साथ-साथ आम नागरिकों को उठाना पड़ता है। दिल्ली हो, मुंबई हो, चेन्नई हो या अन्य महानगर हों या कोई भी बड़े शहर हों सभी में यह स्थिति देखने को मिल रही है। पूरे साल सीवर लाइन के माध्यम से जो गंदा पानी इनमें बहता है वह भी नहीं निकल पाता है। क्योंकि गंदा पानी ज्यादा निकलता है उसकी सफाई नहीं हो पाती है। जिसके कारण साल भर सीवर लाइन के चेंबर से गंदा पानी रोड पर बहता रहता है। जो संक्रमण फैलाने और बीमारियों का कारण भी बनता चला जा रहा है। नगरीय संस्थाओं के इंजीनियर, राज्य सरकारें और भारत सरकार जो योजना बनाती हैं उन योजनाओं का क्रियान्वयन ठीक तरीके से नहीं होता है। विशेष रूप से सीवर लाइन के मामले में सारे इलाकों में पानी के बहाव को लेकर सर्वे करने के पश्चात काम करना चाहिए था, ऐसा नहीं होने के कारण गंदगी से मुक्ति तो मिली नहीं अब हर समय गंदगी और बरसात में जल प्लावन का दंस नागरिकों को झेलना पड़ रहा है। हर बारिश में नागरिकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इसके साथ-साथ घर छोड़कर अन्य जगहों पर जाकर रहने के लिए विवश होना पड़ रहा है। भारत सरकार और राज्य सरकारों को चाहिए कि शहरों में जो भी सीवर लाइन बिछाई गई हैं उनका व्यापक सर्वेक्षण कराया जाए। जल निकासी के लिए बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। शहरों का विकास इस तरह से किया जाए कि साल भर जो गंदा पानी लोगों के घरों से निकलता है वह सीवर लाइनों के माध्यम से ट्रीटमेंट प्लांट तक सही तरीके से पहुंचे। सीवर लाइन समय-समय पर साफ हों। पानी का ढलान पर्याप्त हो। बारिश का पानी भी आसानी के साथ बाहर निकल सके। इसकी व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना जरूरी हो गया है। जिस तरह के हालात हर बारिश में बनते हैं, उससे सभी को बड़ा नुकसान हो रहा है।

# पुलों का ढहना शासन-तंत्र की भ्रष्टता का प्रमाण

*ललित गर्ग*

बिहार में एक पखवाड़े के भीतर लगभग एक दर्जन छोटे-बड़े पुलों के ध्वस्त होने की घटनाएं हैरान करने के साथ-साथ चिंतित करने वाली हैं। जैसी खबरें हैं, अकेले बुधवार, यानी 3 जुलाई को ही राज्य के विभिन्न हिस्सों में पांच पुल-पुलिया धराशायी हो गए। इनमें सिवान में छाड़ी नदी पर बने दो पुल शामिल हैं। इससे पहले दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टर्मिनल-1 पर छत गिरने की घटना से भी हर कोई हैरान है। इस हादसे के कारण अनेक वाहन क्षतिग्रस्त हुए एवं एक व्यक्ति की मौत हो गई और 8 लोग घायल हुए थे। सभी को इस बात की हैरानी हो रही है कि देश के सबसे प्रमुख हवाईअड्डे पर इस तरह का हादसा कैसे हो सकता है? मुंबई में भी घाटकोपर का होर्डिंग गिरना 14 लोगों की मौत का कारण बना था। इन पुलों के गिरने एवं अन्य सरकारी निर्माणों के ध्वस्त होने की घटनाओं ने एक बार फिर यही साबित किया है कि निर्माण कार्यों में फैले व्यापक भ्रष्टाचार और शासन तंत्र में बैठे लोगों की मिलीभगत के बीच ईमानदारी, नैतिकता, जिम्मेदारी या संवेदनशीलता जैसी बातों की जगह नहीं है। आज हमारी व्यवस्था चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो, पारिवारिक हो, धार्मिक हो, औद्योगिक हो, शैक्षणिक हो, चरमरा गई है, दोषग्रस्त हो गई है। उसमें दुराग्रही इतना तेज चलते हैं कि ईमानदारी बहुत पीछे रह जाती है। जो सद्प्रयास किए जा रहे हैं, वे निष्फल हो रहे हैं। पुल के गिरने से जितने पैसों की बर्बादी हुई, उसकी भरपाई आखिर किससे कराई जाएगी? बिहार में पुल गिरने की ताजा घटनाएं कोई पहली नहीं है। इससे पहले पिछले साल भर में सात पुलों के ढह जाने की खबरें आईं थी।

जाहिर है, इन पुलों के ढहने एवं गिरने से कई गांवों का आपस में सीधा संपर्क टूट गया है और मानसून के मौसम में उनकी परेशानियां बढ़ गई हैं। बरसात के मौसम में जर्जर ढांचों के गिरने की घटनाएं ज्यादा घटती हैं और इसीलिए सभी राज्यों में स्थानीय प्रशासन मानसून आने से पहले ही उनकी पहचान कर उनका इस्तेमाल प्रतिबंधित कर देता है। मगर पुल कोई रिहाइशी इमारत नहीं, जिसमें चंद परिवार या कुछ लोग रहते हों, और जिसे एहतियातन खाली करा लिया जाए। ये पुल ग्रामीण लोगों के जीवन की अनिवार्यता एवं जीवनरेखाएं हैं। उच्च तकनीक और प्रौद्योगिकी के मौजूदा समय में उच्च लागत के बावजूद छोटी नदियों और नहरों पर बनने वाले पुल भी यदि चंद वर्षों में या बनते ही धराशायी हो जाएं, तो इसको कुदरती कहर का नतीजा नहीं, आपराधिक मानवीय लापरवाही, भ्रष्टाचार एवं सरकारी धन का दुरुपयोग ही मानना चाहिए। बिहार में सिवान की जिस नदी पर दो पुलों के ढहने की घटना घटी है, वह मृत हो चुकी थी और उसे जल-जीवन हरियाली अभियान के तहत पुनर्जीवित किया गया था। निस्संदेह, इसके लिए राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन सराहना के पात्र हैं। आखिर इस नदी के जिंदा होने से हजारों एकड़ भूमि की सिंचाई को बल मिला है। मगर क्या उसी तंत्र को यह भी नहीं सुनिश्चित करना चाहिए था कि जो पुल जर्जर अवस्था में हैं, उनका विकल्प भी साथ-साथ तैयार किया जाए?

इस तरह बार-बार पुलों का गिरना एवं ध्वस्त होना सरकार में गहरे पैठ चुके भ्रष्टाचार, लापरवाही एवं रिश्वतखोरी को उजागर करता है। आजादी के अमृत-काल में पहुंचने के बाद भी भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, बेईमानी हमारी व्यवस्था में तीव्रता से व्याप्त है, अनेक हादसों एवं जानमाल की हानि के बावजूद भ्रष्ट हो चुकी मोटी चमड़ी पर कोई असर नहीं होता। ये पुल हादसें एवं ध्वस्त होने की घटनाएं बिहार में सरकारी भ्रष्टाचार के चरम पर होने को ही बल देती है। ऐसा नहीं है कि बिहार में ही ऐसे हादसें हो रहे हैं। गुजरात के मोरबी पुल हादसे को लोग अब भी नहीं भूले हैं। इस हादसे में 135 लोगों की मौत हो गई थी। सात साल पहले कोलकाता में विवेकानंद पुल के ढहने से 26 लोगों की मौत की घटना भी सबको याद होगी। सिर्फ बिहार में पुलों का यूं ढहते जाना ही चिंता की बात नहीं है, दूसरे तमाम राज्यों से भी चमचम सड़कों पर बनते गड्ढों और नए निर्माण के दरकने की खबरें लगभग रोजाना सुर्खियां बटोर रही हैं। इसलिए बेहतर होगा कि तमाम सार्वजनिक निर्माण में पारदर्शिता, ईमानदारी एवं आधुनिक स्थापित मानकों की गारंटी सुनिश्चित की जाए और इसमें किसी किस्म की कोताही बरतने वाले की जिम्मेदारी तय हो। देश भर में तमाम पुराने पुलों की समीक्षा के साथ-साथ उनके रखरखाव या वैकल्पिक पुल के निर्माण को लेकर ठोस कदम उठाए जाने चाहिए।

इतना तय है कि ये सभी पुल अगर भरभरा कर गिर रहे हैं तो इनकी डिजाइन गलत होने से लेकर उसमें उपयोग होने वाली सामग्री के घटिया होने का भी साफ संकेत है। लेकिन जिस तरह सरकार इन एवं ऐसे पुलों की गुणवत्ता और जोखिम का अध्ययन करा रही थी, क्या उसके निर्माण के दौरान या उससे पहले डिजाइन सहित उसके हर कसौटी पर बेहतर होने के लिए जांच कराना सुनिश्चित नहीं कर सकती थी? यह तय है कि इन पुलों के निर्माण में व्यापक खामियां थीं और वे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गये। सवाल है कि जब सरकार किसी कंपनी को पुल निर्माण की जिम्मेदारी सौंपती हैं, उससे पहले क्या गुणवत्ता की कसौटी पर पूरी निर्माण योजना, डिजाइन, प्रक्रिया, सामग्री, समय-सीमा और संपूर्णता को सुनिश्चित किया जाना जरूरी समझा जाता?

देश में भ्रष्टाचार सर्वत्र व्याप्त है, विशेषतः राजनीतिक एवं प्रशासनिक भ्रष्टाचार ने देश के विकास को अवरूद्ध कर रखा है। यही कारण है कि पुल या दूसरे निर्माण-कार्यों के लिए रखे गए बजट का बड़ा हिस्सा कमीशन-रिश्वतखोरी की भेंट चढ़ जाता है। इसका सीधा असर निर्माण की गुणवत्ता पर पड़ता है। निर्माण घटिया होगा तो फिर उसके धराशायी होने की आशंका भी बनी रहती है। हादसों का एक बड़ा कारण जांच में दोषी और जिम्मेदार ठहराए गए अधिकारियों एवं ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का न होना भी है। बिहार, दिल्ली, मुम्बई, गुजरात हादसों के दोषियों को बचाने के प्रयास भी सबके सामने हुए हैं। हर हादसे के बाद लीपापोती के प्रयास खूब होते हैं। हादसे में मरने वालों के परिजनों को मुआवजा बांटकर ही अपनी जिम्मेदारी पूरी समझने वाली सरकारों को इससे आगे बढ़ना होगा। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर निगरानी रखने की पारदर्शी नीति नियामक केन्द्र बनाने के साथ उस पर अमल भी जरूरी है। विकसित देशों में भी ऐसे हादसे होते हैं, लेकिन अंतर यह है कि भारत में ऐसे हादसों से सबक नहीं लिया जाता। यह प्रवृत्ति दुर्भाग्यपूर्ण है। विडम्बना देखिये कि ऐसे भ्रष्ट शिखरों को बचाने के लिये सरकार कितने सारे झूठ का सहारा लेती है।

हादसों की जांच से काम नहीं चलने वाला। ऐसे निर्माण कार्यों में कमीशन-रिश्वतखोरी रोकने पर खास ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि जब ठेकेदार एक बड़ी राशि कमीशन के तौर पर दे देता है, तो फिर वह निर्माण कार्य में भी गुणवत्ता बनाए रखने के प्रति लापरवाह हो जाता है। लापरवाही की परिणति ऐसे हादसों के रूप में सामने आती है। प्रगतिशील कदम उठाने वाले नेतृत्व ने अगर भ्रष्ट व्यवस्था सुधारने में मुक्त मन से सहयोग नहीं दिया तो कहीं हम अपने स्वार्थी उन्माद एवं भ्रष्टता में कोई ऐसा धागा नहीं खींच बैठें, जिससे पूरा कपड़ा ही उधड़ जाए। राजनीति के क्षेत्र में भ्रष्टाचार के मामले में एक-दूसरे के पैरों के नीचे से फट्टा खींचने का अभिनय तो सभी दल एवं नेता करते हैं पर खींचता कोई भी नहीं। रणनीति में सभी अपने को चाणक्य बताने का प्रयास करते हैं पर चन्द्रगुप्त किसी के पास नहीं है। घोटालों और भ्रष्टाचार के लिए हल्ला उनके लिए राजनैतिक मुद्दा होता है, कोई नैतिक आग्रह नहीं। कारण अपने गिरेबार में तो सभी झांकते हैं वहां सभी को अपनी कमीज दागी नजर आती है, फिर भला भ्रष्टाचार से कौन निजात दिरायेगा? ऐसी व्यवस्था कब कायम होगी कि जिसे कोई 'रिश्वत' छू नहीं सके, जिसको कोई 'सिफारिश' प्रभावित नहीं कर सके और जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सके। ईमानदारी अभिनय करके नहीं बताई जा सकती, उसे जीना पड़ता है कथनी और करनी की समानता के स्तर तक। आवश्यकता है, राजनीति के क्षेत्र में जब हम जन मुखातिब हों तो प्रामाणिकता का बिल्ला हमारे सीने पर हो। उसे घर पर रखकर न आएं। राजनीति के क्षेत्र में हमारा कुर्ता कबीर की चादर हो। तभी इन भ्रष्ट पुलों का भर-भराकर गिरना बन्द होगा।

युग पुरुष आश्रम में 6 बच्चों की मौत का मामला :

# पीएमओ ने इंदौर भेजा जांच दल

**इन्दौर।** युग पुरुष आश्रम में छह बच्चों की मौत का मामला अब राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने मामले में संज्ञान लेकर जांच दल को इंदौर भेजा है। शनिवार को टीम ने इंदौर में दस्तावेज और कंप्यूटर की हार्ड डिस्क जांच में ली है। साथ ही यहां की जांच में क्या मिला उसके दस्तावेज भी हासिल किए हैं। अब मामले की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर सबमिट की जाएगी।

**बच्चों को लेकर पीएम मोदी संवेदनशील** –जांच टीम की सदस्य डॉ. दिव्या गुप्ता ने कहा कि अब मामला इंदौर का नहीं राष्ट्रीय स्तर का हो गया है। दिव्या ने कहा कि बच्चों को कितनी गंभीरता से लेना चाहिए इसे लेकर पीएम मोदी हमेशा संवेदनशील रहते हैं। उन्होंने आग्रह किया है कि इस विषय को लेकर आप पूरी तहकीकात करके आएं। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने रिपोर्ट मांगी है। उनकी ओर से पीएमओ को रिपोर्ट जानी है। पीएमओ से रिपोर्ट भेजने को कहा गया है।

**दिल्ली में सभी दस्तावेज का होगा एनालिसिस**–डॉ. दिव्या गुप्ता ने कहा कि हम बहुत सारे दस्तावेज साथ में लेकर दिल्ली जा रहे हैं। डॉक्टरों ने जो निरीक्षण-परीक्षण किया था। उसकी जांच के भी पेपर्स हैं। इसमें मिर्गी की दवाइयों का जो परीक्षण कर रहे थे, उसकी डिटेल्स रिपोर्ट भी है। जो ऑडिट आया है उसकी भी डिटेल्स है। पूरा पेपर वर्क और हार्ड डिस्क साथ में लेकर जा रहे हैं। दिल्ली में सभी दस्तावेज का एनालिसिस होगा। इसके बाद राज्य और केंद्र सरकार को रिपोर्ट सबमिट करनी है। डॉ. गुप्ता ने इंदौर के अधिकारियों पर सवाल उठाए हैं। दिव्या का कहना है कि अधिकारी अपनी जिम्मेदारी पर खरे नहीं उतर पाए। इस केस में हर चीज का पहलू है। उसकी डिटेल्स में जानकारी लेंगे। इसके बाद हम सरकार से अनुशंसा करेंगे कि किस तरह का स्टेप लेना है। कलेक्टर ने शोकाज नोटिस तो दे दिया है और तुरंत एक्शन भी लिया है। अब आगे देखना है। बाकी एक्शन निश्चित तौर पर होगा। बच्चों की देखभाल को लेकर समाज को सजग होना पड़ेगा।

## फोटोग्राफी, इनकम टैक्स सहित 6 ऑनलाइन कोर्स तैयार, सितंबर से शुरू होंगी कक्षाएं

**इंदौर।** देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने 6 नए ऑनलाइन कोर्स तैयार किए हैं। ये मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस (मूक्स) के माध्यम से रहअअट पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे, जिसमें फोटोग्राफी, टैक्स और विज्ञापन पर पाठ्यक्रम आधारित है। इनके लिए अगले सप्ताह से पंजीयन शुरू हो चुके हैं। इसमें देशभर के विद्यार्थी आवेदन कर रहे हैं। ऑनलाइन पाठ्यक्रम की कक्षाएं सितंबर से शुरू की जाएंगी। विश्वविद्यालय प्रशासन के मुताबिक ये पाठ्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड रिसर्च सेंटर (ईएमआरसी) ने बनाए हैं, जिसमें विषय विशेषज्ञों ने कंटेंट तैयार किया है। बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी, इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, इंट्रोडक्शन टू एडवरटाइजिंग, सोशियोलाजी आफ किनशिप, बेसिक्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग पाठ्यक्रम बनाए हैं। इन्हें मिलाकर विश्वविद्यालय अभी तक 40 से ज्यादा पाठ्यक्रम बना चुका है।

**ये होगा शुल्क**– ऑनलाइन पाठ्यक्रम के माध्यम से अध्ययन करने वाले इच्छुक विद्यार्थी पोर्टल पर जाकर निशुल्क रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अंतिम तिथि 31 अगस्त 2024 है। अधिकारियों के मुताबिक सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूर्ण होने के बाद प्रमाण-पत्र भी प्रदान किए जाएंगे। प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए सामान्य वर्ग को 1000 और आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों को 500 शुल्क देना होगा।

**विद्यार्थियों के लिए काफी ज्यादा उपयोगी**– कुलगुरु प्रो. रेणु जैन का कहना है कि विश्वविद्यालय इस राष्ट्रीय स्तर की परियोजना में शामिल होकर एक महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है।

## इस्कॉन की जगन्नाथ रथयात्रा का 50 मंचों से पुष्प वर्षा कर हुआ स्वागत

**इन्दौर।** विमानतल मार्ग स्थित श्री श्रीविद्याधाम मंदिर से रविवार दोपहर निकली इस्कॉन की जगन्नाथ रथयात्रा ने राजबाड़ा स्थित गोपाल मंदिर तक करीब सात किलोमीटर लंबे यात्रा मार्ग को हरे रामा हरे कृष्णा संकीर्तन और भक्ति की रसधारा से सराबोर बनाए रखा। इस्कॉन मंदिर इंदौर के अध्यक्ष स्वामी महामनदास, महामंडलेस्वर दादू महाराज, अखंडधाम के महामंडलेश्वर डॉ. स्वामी चेतन स्वरूप के सानिध्य में वरिष्ठ समाज सेवी विनोद अग्रवाल, प्रेमचंद गोयल, टीकमचंद गर्ग, विष्णु बिंदल, पवन सिंघानिया आदि ने सुसज्जित हाईड्रोलिक रथ का पूजन कर इस रथयात्रा का शुभारंभ किया और स्वर्ण निर्मित झाड़ू से यात्रा मार्ग बुहारने की भी शुरूआत की। शहर के अनेक धार्मिक, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, राजनेता एवं विद्वान भी इस यात्रा में भागीदार बने। समूचे मार्ग में करीब 50 स्वागत मंचों से भक्तों एवं तीनों रथों पर पुष्प वर्षा कर भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा एवं भाई बलभद्र के विग्रह का पूजन भी किया गया। देश-विदेश से आए इस्कॉन से जुड़े भक्तों ने भी समूचे मार्ग में अपनी भजन मंडलियों की मनोहारी प्रस्तुतियों से माहौल को पूरे समय भक्तिभाव से भरपूर बनाए रखा। रथयात्रा में शहर के 25 हजार से अधिक सभी वर्गों और धर्मों के श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस्कॉन मंदिर इंदौर के अध्यक्ष स्वामी महामनदास सहित अनेक संत दोपहर में 51 फीट ऊंचा रथ लेकर विद्याधाम मंदिर पहुंचे, जहां पहले से जमा भक्तों के सैलाब ने भजनों पर नाचने-गाने का सिलसिला शुरू कर दिया। पश्चिम क्षेत्र में दूसरी बार निकली इस यात्रा में शामिल भक्तों का उत्साह देखते ही बनता था। रथ की पुष्प सज्जा वृंदावन से आए कलाकारों ने की।

मध्य क्षेत्र में ट्रैफिक सुचारू करने के लिए की जा रही पहल

# राजबाड़ा के आसपास नो पार्किंग झोन बनाएगा नगर निगम

**इंदौर।** शहर का मध्य क्षेत्र अर्थात राजबाड़ा क्षेत्र में ट्रैफिक सुचारू करने के लिए नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस नई पहल कर रहे हैं। यातायात को सुचारू और निर्बाध रूप से चलने के लिए निगम अब राजबाला और उसके आसपास के क्षेत्र को नो पार्किंग झोन बनाने वाला है। इसके लिए लगभग सभी तैयारियां कर ली गई है। नंदलालपुरा सब्जी मंडी में ही एक हाईटेक पार्किंग भी बनाई गई है। इसमें राजबाड़ा और उसके आसपास के व्यापारिक क्षेत्र की में आने वाले वाहनों को पार्किंग की सुविधा दी गई है। चूंकि राजबाड़ा क्षेत्र प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र में शुमार है, इसलिए शहर ही नहीं आसपास के जिलों से भी लोग यहां सामान खरीदने आते हैं। इन लोगों के सामने वाहन पार्किंग की एक प्रमुख समस्या रहती है। इन्हें सुविधा देने की दृष्टि से नंदलालपुरा सब्जी मंडी में ही आधुनिक पार्किंग बनाई गई है। निगम अधिकारियों के अनुसार राजबाड़ा और उसके आसपास के क्षेत्र को नो पार्किंग जोन बनाने के लिए हाल ही में एक बैठक भी हुई है। इसमें निगम और ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी शामिल हुए। मुख्य रूप से बैठक में राजबाड़ा और उसके आसपास के क्षेत्र में ट्रैफिक का निकलते कचूमर को खत्म करने को लेकर मंथन किया गया। इसके लिए सबसे पहले यह तय किया गया कि राजबाड़ा और उसके आसपास की दुकानदारों के वहां आने वाले वाहनों को सुव्यवस्थित पार्किंग उपलब्ध कराई जाए। निगम अधिकारियों द्वारा इसके विकल्प के रूप में नंदलालपुरा सब्जी मंडी में बनाई गई पार्किंग को भी सामने लाया गया। हालांकि सूत्र बताते हैं कि नो पार्किंग जोन बनाने को लेकर ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम अधिकारियों में पूर्ण रूपेण सहमति नहीं बनी है लेकिन फिर भी यह माना जा रहा है कि राजवाड़ा क्षेत्र को जल्द ही नो पार्किंग जोन किया जा सकता है।

### सुभाष मार्केट में भी पार्किंग, लेकिन पड़ी रहती खाली

हालांकि राजबाड़ा के ठीक पीछे सुभाष मार्केट में भी एक पार्किंग बनाई गई है। यह पुरानी होकर राजबाड़ा के बिल्कुल पास है, लेकिन फिर भी लोग सड़कों के किनारे ही वहां पर करने की आदत से बाज नहीं आते हैं। इसे खत्म करने के लिए भी निगम और पुलिस प्रशासन तैयारी कर रहा है। यह हटाई किया गया है कि मध्य क्षेत्र में एलाउंसमेंट कर कर यह बताया जाएगा की राजवाड़ा और उसके आसपास के क्षेत्र को नो पार्किंग जोन बनाया गया है। यह अभी बताया जाएगा की वाहन चालक अपने वाहन निर्धारित पार्किंग में खड़े करें।

### निगम की आमदनी में हो जाएगी बढ़ोतरी

नंदलालपुरा पार्किंग में वहां खड़े करने के लिए वाहन चालकों को भारी भरकम शुल्क भी अदा करना होगा। इससे निगम की आमदनी में भी इजाफा हो जाएगा। यदि पार्किंग सही-सही संचालित होती रही तो निगम को आई के एक और स्रोत में वृद्धि हो जाएगी। निगम अधिकारियों की माने तो इस कारण भी निगम चाहता है कि राजबाड़ा क्षेत्र को नो पार्किंग झोन घोषित कर दिया जाए।

# देरी से दफ्तर आने वाले शिक्षा विभाग के 17 कर्मचारियों का वेतन कटेगा

**इंदौर।** देरी से आफिस आने वाले शिक्षा विभाग के 17 अधिकारी-कर्मचारियों का एक दिन का वेतन काटा जाएगा। इसके लिए सीईओ जिला पंचायत सिद्धार्थ जैन ने आदेश जारी कर दिया है। कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का निरीक्षण किया गया। इस दौरान ये कर्मचारी-अधिकारी देरी से आफिस पहुंचे थे। जानकारी अनुसार आशीष सिंह कलेक्टर के निर्देश पर स्कूल शिक्षा विभाग के 17 अधिकारी-कर्मचारियों और व्याख्याताओं का एक दिन का वेतन काटा जाएगा। बताया जाता है कि पिछले शुक्रवार को कलेक्टर सिंह के निर्देश पर सभी शासकीय कार्यालयों में अधिकारियों कर्मचारियों एवं अन्य के कार्यालय आने और जाने के समय की आकस्मिक जांच की गई थी। इसमें स्कूल शिक्षा विभाग की सहायक संचालक सुषमा वैश्य, जिला खेल अधिकारी घनश्याम करोले सहित 17 अधिकारी-कर्मचारी और व्याख्याता समय पर कार्यालय नहीं पहुंचे थे। इन सभी का एक दिन का वेतन काटने के जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने निर्देश दिए हैं।

## इंदौर नगर निगम में पहली बार एक साथ बदले गए सभी जोनल अधिकारी

**इंदौर।** इंदौर नगर निगम ने एक साथ शहर के सभी जोनों में बदलाव कर दिया है। शनिवार को निगमायुक्त ने आदेश जारी कर सभी जोनल अधिकारियों के साथ भवन अधिकारी, भवन निरीक्षकों को भी बदल दिया। साथ में तीन नए जोन भी सूची में जोड़ गए हैं। अब तक नगर सीमा को 19 जोनों में बांट रखा था। ताजा सूची में 22 जोनल अधिकारियों के साथ भवन अधिकारी और भवन निरीक्षकों को पदस्थापना दी गई है। खास बात है कि ताजा सूची में जोनों की जिम्मेदारी नए लोगों को दी गई है। कई पुराने और अनुभवी लोगों को हटाकर लूप लाइन में डाल दिया गया है।

### चुनाव रिजल्ट की समीक्षा के बाद भाजपा में होगा बड़ा ऑपरेशन

# प्रदेश प्रभारी बदलने के बाद अब संगठन गढ़ने की बारी

***भोपाल।*** *विधानसभा के बाद लोकसभा चुनाव में मिली रिकॉड जीत के बाद भाजपा आलाकमान ने अब प्रदेशों के संगठन को और मजबूत करने पर ध्यान केंद्रीत किया है। इसी कड़ी में गत दिनों मप्र सहित 24 राज्यों के प्रदेश प्रभारियों को बदला गया। लोकसभा चुनाव के प्रभारी डॉ. महेंद्र सिंह और सह प्रभारी सतीश उपाध्याय को ही मप्र की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब संभावना जताई जा रही है कि जल्द की प्रदेश संगठन में बदलाव किया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि रविवार को राजधानी में मप्र भाजपा कार्यसमिति की बैठक में चुनाव रिजल्ट की समीक्षा के बाद संगठन में बदलाव पर फोकस किया जाएगा।*

रवींद्र भवन में रविवार को मप्र भाजपा कार्यसमिति बैठक में पहली बार एक हजार से ज्यादा मंडल अध्यक्ष भी शामिल हुए। पार्टी के आगे के कार्यक्रमों की रूपरेखा के साथ इस बैठक का खास फीचर रहा उन कार्यकर्ताओं का धन्यवाद जिन्होंने भाजपा को ये एतिहासिक जीत दिलाई। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भाजपा को मिली एतिहासिक जीत के बाद ये पहली कार्यसमिति की बैठक हुई। इस कार्यसमिति में केन्द्र के कार्यक्रमों पर चर्चा हई।

## महेंद्र और सतीश की जोड़ी का दिखेगा असर

-भाजपा ने केंद्र में नई सरकार के बनते ही मप्र में बदलाव की शुरूआत कर दी है। शुरूआत प्रभारी एवं सह प्रभारी से की गई है। सौ प्रतिशत रिजल्ट देने वाले लोकसभा चुनावों के प्रभारी डॉ. महेंद्र सिंह और सह प्रभारी सतीश उपाध्याय को ही मप्र की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रभारियों की नियुक्ति के बाद में प्रदेश संगठन स्तर पर बड़ा बदलाव किया जा सकता है। संभावना जताई जा रही है कि प्रदेश संगठन के गठन में डॉ. महेंद्र सिंह और सतीश उपाध्याय की जोड़ी का प्रभाव देखने को मिलेगा। संकेत पुख्ता होते ही दावेदारों को लेकर भी प्रदेश में कयास बढ़ गए हैं। लोकसभा चुनाव और नई सरकार के गठन के साथ ही भाजपा में संगठन स्तर पर व्यापक बदलाव की संभावना जताई जा रही थीं। इसकी शुरूआत राष्ट्रीय संगठन ने मप्र में प्रभारी व सह प्रभारी बदलकर की है। अब तक संगठन के प्रभारी रहे पी मुरलीधर राव प्रभारी की जिम्मेदारी से मुक्त हो गए हैं। उनके स्थान पर यूपी के एमएलसी डॉ महेंद्र सिंह (एमएलसी) प्रभारी तथा दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष सतीश उपाध्याय बीजेपी के सह प्रभारी बनाए गए हैं। इस जोड़ी ने लोकसभा चुनावों के दौरान प्रदेश में खासी मेहनत की थी। बूथ स्तर तक पहुंचकर दोनों कार्यकर्ताओं की बैठकें कर रणनीति बनाने में अहम भूमिका निभाई। हर जिले में संगठन के नेता और कार्यकर्ताओं के बीच दोनों की पहचान भी हो चली है। साथ ही संगठन के नेताओं से तालमेल भी छह महीने में बना है। उपाध्याय को तो 2019 के चुनाव में भी प्रदेश का सहप्रभारी बनाया गया था। विधानसभा चुनाव केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को मध्यप्रदेश का प्रभारी और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को सह प्रभारी बनाया था।

## संगठन में दिखेगा इनका दम

गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में 29 की 29 सीटें जीतकर मप्र भाजपा ने पूरे देश को चौंका दिया। इस वजह से सत्ता के बाद अब संगठन में मध्य प्रदेश भाजपा का दबदबा बढ़ेगा। एमपी के नेताओं को केंद्रीय संगठन में जगह मिल सकती है। संगठन में जिन्हें जगह मिल सकती है उनमें प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा, अरविंद भदौरिया, जयभान सिंह पवैया सहित कई नेताओं के नाम की चर्चा है। इन नेताओं को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। पार्टी पदाधिकारियों का कहना है कि सत्ता हो या संगठन भाजपा में हमेशा प्रदेश के नेताओं का दबदबा रहा है। पदाधिकारियों ने कहा कि जिस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व ने राज्य के पांच नेताओं को मंत्री बनाया है, उसी तरह आने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी मप्र के बड़े नेताओं को जगह मिलेगी। भाजपा एक ऐसी पार्टी है, जहां कार्यकर्ता सत्ता की जगह संगठन में काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। इसे लेकर कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि मप्र में भाजपा के कई नेता बेरोजगार हो गए हैं। जो नेता विधानसभा में चुनाव हारे और इस उम्मीद में रहे लोकसभा में उन्हें पार्टी टिकट देगी, उनकी उम्मीद पूरी नहीं हुई। ऐसे में अब ये लोग अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह चाहते हैं। इसके लिए वे लगातार लॉबिंग कर रहे हैं।

## नेताओं को मिली थी इतनी बड़ी जिम्मेदारी

गौरतलब है कि वीडी शर्मा को पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी थी। उन पर वोट शेयर बढ़ाने, मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक आकर्षित करने, युवाओं जोडने और सभी सीटें जिताने की जिम्मेदारी थी। शर्मा ने इन सभी जिम्मेदारियों को निभाया। इसका नतीजा रहा कि पूरे देश में मप्र इकलौता राज्य है जहां भाजपा ने क्लीन स्वीप किया। शर्मा खुद अपनी सीट से 5 लाख 31 हजार 229 वोटों से जीते। इसी तरह पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा को नई जॉइनिंग कमेटी का जिम्मा दिया गया था। उन्होंने पूरे प्रदेश में भाजपा में सदस्यता अभियान चलाया और कई लोगों को पार्टी में जोड़ा। खास बात यह रही कि, इस दौरान कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता और दिग्गज नेता भी भाजपा में शामिल हो गए। इस अभियान ने भाजपा की जीत में बड़ी भूमिका निभाई।

# मरीज़ों को सहज एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं का प्रदाय सुनिश्चित करें: उप-मुख्यमंत्री श्री शुक्ल

### चिकित्सा महाविद्यालय के अधिष्ठाताओं ने विभाग के सशक्तिकरण के प्रयासों के लिए किया आभार व्यक्त

**भोपाल।** उप-मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल से मध्यप्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों के अधिष्ठाताओ ने भोपाल के निवास कार्यालय में सौजन्य भेंट की। अधिष्ठाताओं ने पे-प्रोटेक्शन, लीव-प्रोटेक्शन, सर्विस-प्रोटेक्शन और नॉन-प्रैक्टिसिंग एलाउंस के बारे में उप-मुख्यमंत्री श्री शुक्ल द्धारा किये जा रहे प्रयासों के लिये आभार व्यक्त किया। उप-मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने निर्देश दिये कि चिकित्सा महाविद्यालयों में छात्रों की शिक्षा बेहतर करने के लिये प्रयास करें। समस्त अधिष्ठाता अस्पताल के अधीक्षकों के साथ समन्वय कर मरीजों को सहज और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सकीय सेवाओं के प्रदाय के लिए व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करें। उप-मुख्यमंत्री श्री शुक्ल को अधिष्ठाताओं ने महाविद्यालय के संचालन, अधोसंरचणात्मक विकास एवं उन्नयन, प्रशासनिक व्यवस्था, वित्तीय आवश्यकता और मेंटेनेंस सहित अन्य महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के संबंध में अवगत कराया। उप-मुख्यमंत्री ने शीघ्र आवश्यक सहयोग मुहैया कराने की बात कही।

मेडिकल कॉलेज में प्रशासकीय अधिकारी (वित्त) की नियुक्ति, महाविद्यालयों के उन्नयन, हॉस्टल और अस्पतालों के सिविल और इलेक्ट्रिक उपकरणों के मेंटेनेंस, लेक्चर हॉल और प्रदर्शक रूम को स्मार्ट क्लास में विकसित करने के लिये बजट उपलब्ध कराने का अधिष्ठाताओं ने अनुरोध किया। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में सहभागिता के लिये नीति बनाने का अनुरोध किया ताकि चिकित्सा शिक्षक और छात्र अपनी रिसर्च को विश्वस्तरीय प्लेटफार्म पर प्रस्तुत कर सकें। बैठक में डॉ प्रमेंद्र सिंह ठाकुर अधिष्ठाता बीएमसी सागर, डॉ. कविता सिंह अधिष्ठाता जीएमसी भोपाल, डॉ. धाकड अधिष्ठाता ग्वालियर,डॉ सुनील अग्रवाल अधिष्ठाता रीवा, डॉ. परमहंस अधिष्ठाता शिवपुरी, डॉ. मनीष निगम अधिष्ठाता विदिशा और डॉ मरावी अधिष्ठाता दतिया शामिल हुए।

# उद्यमिता को बढ़ावा देने में एम्स भोपाल प्रतिबद्ध

**भोपाल।** कार्यपालक निदेशक प्रो. डॉ. अजय सिंह के दूरदर्शी नेतृत्व में, एम्स भोपाल ने अपने स्नातक छात्रों के बीच अनुसंधान और उद्यमिता की संस्कृति को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया है। इस प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए, एमबीबीएस छात्र ईशान पवार, तिथि शाह और दिव्यांश शर्मा को प्रतिष्ठित बीआईआरएसी ई-युवा फेलोशिप योजना के लिए चुना गया है। बीआईआरएसी ई-युवा (उत्साही शोध के माध्यम से युवा नवाचार को प्रोत्साहित करना) फेलोशिप एक अत्यधिक प्रतिष्ठित कार्यक्रम है, जो जैव प्रौद्योगिकी में युवा नवप्रवर्तकों को पोषित करता है। चयनित छात्रों की परियोजना का उद्देश्य गहरे गुहाओं और खराब दृश्यता वाले क्षेत्रों में आसान टांका लगाने के लिए एक चुंबकीय जांच विकसित करना है।

यह अभिनव उपकरण सर्जिकल सटीकता और दक्षता को बढ़ाने का लक्ष्य रखता है, जो चिकित्सा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण चुनौती का समाधान है। यह परियोजना एम्स भोपाल के यूरोलॉजी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. कुमार माधवन के मार्गदर्शन में की गई थी।

एम्स भोपाल में प्रो. डॉ. अजय सिंह का नेतृत्व संस्थान की स्नातक छात्रों के बीच नवाचारी अनुसंधान और उद्यमिता कौशल को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। बीआईआरएसी ई-युवा फेलोशिप जैसी अवसरों को प्रदान करके, एम्स भोपाल अपने छात्रों को चिकित्सा नवाचार में अग्रणी बनने और स्वास्थ्य सेवा उद्योग में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए सशक्त बना रहा है।

### 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान

# पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम-उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल

## उप-मुख्यमंत्री ने माँ की स्मृति में पौधरोपण किया

**भोपाल।** उप-मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह अभियान आज एक जन-आंदोलन बन गया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के आह्वान पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश ने 5 करोड़ 50 लाख पौधरोपण का संकल्प लिया है। विगत दिनों भोपाल में एक दिन में रिकॉर्ड 12 लाख पौधे रोपे गए। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में इंदौरवासियों ने 51 लाख पौधरोपण का संकल्प लिया है। उप-मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि यह अभियान प्रकृति के प्रति हमारे कर्तव्यों को रेखांकित करता है, सेवा करने का अवसर प्रदान करता है। उप-मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने भोपाल में चार इमली स्थित निवास के सम्मुख अपनी माताजी की स्मृति में बरगद के पौधे का रोपण किया। उप-मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अभियान में सहभागिता कर पौधरोपण करने और उनका संरक्षण करने की अपील की है। उप-मुख्यमंत्री श्री शुक्ल के साथ सांसद भारत सिंह कुशवाह और अन्य जनप्रतिनिधियों ने पौधों का रोपण किया। बरगद, नीम, कदंब सहित अन्य पौधों का रोपण किया गया।

# मप्र में मात्र 500 रूपए मिल रहा मकान भाड़ा भत्ता

**भोपाल।** केंद्रीय कर्मचारियों को अब चार प्रतिशत बढ़कर मकान भाड़ा भत्ता मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों को अब मूल वेतन का 50 प्रतिशत मकान भाड़ा भत्ता मिलेगा। पहले मूल वेतन का 46 प्रतिशत मकान भाड़ा भत्ता मिल रहा था लेकिन मध्य प्रदेश में सातवां वेतनमान लागू होने के बाद भी कर्मचारियों को मात्र 500 मकान भाड़ा भत्ता मिल रहा है, जो देश के सभी राज्यों कर्मचारियो से कम है। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच ने मुख्यमंत्री को पत्र सौंप कर मांग की है कि मप्र के कर्मचारियों को भी केंद्र के कर्मचारियों के समान मूल वेतन का 50 प्रतिशत मकान भाड़ा भत्ता सातवें वेतनमान के अनुरूप दिया जाए। मांग करने वाले कर्मचारी नेताओं में अशोक पांडे, हरि सिंह गुर्जर, लव प्रकाश पाराशर, राजू उपाध्याय, लक्ष्मन शुक्ला, राजकरण चतुर्वेदी, प्रेमलाल त्रिपाठी, योगेंद्र सिंह तोमर आदि शामिल है। मप्र कर्मचारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे ने बताया कि केंद्र सरकार प्रतिवर्ष कर्मचारियों के महंगाई भत्ता गृह भाड़ा भत्ता मेडिकल भत्ता बढ़ा रही है, लेकिन मप्र सरकार प्रदेश के कर्मचारियों का ना तो वेतन बढ़ा रही है ना ही महंगाई भत्ता बढ़ा रही है और ना ही मेडिकल भत्ता बड़ा रही है। राजस्थान में कर्मचारियों को 7200 रुपए प्रतिमाह मकान भाड़ा भत्ता मिल रहा है। छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश में सातवें वेतनमान के अनुरूप मकान भाड़ा भत्ता मिल रहा है, लेकिन मप्र के कर्मचारियों को देश के सभी राज्यों के कर्मचारियों से कम मात्रा 500 प्रतिमाह मकान भाड़ा भत्ता मिल रहा है।

### *समझौते का पालन नहीं*

पांडे ने बताया कि राज्य सरकार ने कर्मचारी संगठनों से समझौता किया था कि प्रदेश के कर्मचारियों को समस्त लाभ केंद्र के कर्मचारियों के सामान दिए जाएगे। लेकिन समझौते के अनुरूप कभी भी सरकार ने कर्मचारियों को भत्तों का लाभ नहीं दिया। अभी भी मप्र राज्य की कर्मचारी केंद्र के कर्मचारियों से चार प्रतिशत महंगाई भत्ता कम प्राप्त कर रहे हैं।

### गांव के युवाओं के लिए रोजगार का अवसर

# अब खेतों की गिरदावरी करेंगे युवा

***भोपाल।*** *सरकार की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में किसानों सहित युवाओं को नई-नई योजनाओं से जोड़कर लाभ प्रदान किया जा रहा है। इसी कड़ी में राज्य सरकार की ओर से ग्रामीण युवाओं को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से सरकारी योजनाओं की गिरदावरी यानी सर्वे का काम कराया जाएगा।*

राज्य सरकार की इस पहल से ग्रामीण युवाओं को गांव में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। राज्य सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद सहित बहुत सी सरकारी योजनाओं में फसलों की गिरादवरी की जाती है। इस काम के लिए अब राज्य सरकार ग्रामीण युवाओं को जोडना चाहती है ताकि फसलों की सही गिरावदरी हो सके और योजना में और पारदर्शिता आए ताकि किसानों को इसका पूरा लाभ मिल सके। इस संबंध में राज्य शासन द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशानुसार फसलों की गिरदावरी के लिए अब युवाओं को भी जोड़ा जाएगा। इसके लिए इच्छुक युवाओं से 10 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। जो भी पढ़े-लिखे युवा इस काम को करना चाहते हैं वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। फसलों की मध्यप्रदेश भू अभिलेख नियमावली के मुताबिक फसल गिरदावरी का काम साल में तीन बार किया जाता है। पहला खरीफ फसल सीजन में, दूसरा जायद फसल सीजन में और तीसरा रबी फसल सीजन में। इस काम को सारा (स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन) एप के जरिये किया जाता है।

इस गिरदावरी या सर्वे का उपयोग उपार्जन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आदि योजनाओं में सतत रूप से किया जाता है। अभी तक यह काम कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा खेत में जाकर किया जाता रहा है। फसल गिरदावरी के काम में पारदर्शिता लाने के लिए भारत सरकार की ओर से डिजिटल क्रॉप सर्वे का कार्य प्रारंभ किया गया है। यह प्रत्येक मौसम के लिए करीब 45 दिन की कार्यवाही होती है। इसमें जिओ फेंस (पार्सल लेवल) तकनीक के जरिये खेत में बोई गई फसल का फोटो खींचकर फसल सर्वेक्षण का काम नियत अंतराल में पूरा किया जाएगा। इस योजना के तहत खरीफ सीजन 2024 डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण के लिए सर्वेयर पंजीयन 10 जुलाई तक किया जाना है। गांव के युवा होंगे चयनित-खेतों के रिकॉर्ड ऑनलाइन करने के लिए युवाओं को प्रति खसरा आठ रुपये दिए जाएंगे। नई व्यवस्था के तहत गांव के कुछ युवाओं को ही पटवारी की जगह खेतों की गिरदावरी कराने के लिए चयनित किया जाएगा। चयनित युवक ही मोबाइल एप की मदद से गिरदावरी का काम पूरा करेंगे। इससे किसानों की फसल का सही रिकॉर्ड किसान चढ़वा सकेंगे।

इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए फर्जी जानकारी भी नहीं दे पाएंगे। इस काम को नीमच और सिवनी जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर वर्ष 2023 में शामिल किया गया था। यहां सफलता मिलने पर प्रदेश के अन्य जिलों में भी इसे लागू किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत सभी 52 जिलों के 53 हजार गांवों के करीब 80 लाख किसानों के खेतों में होने वाली फसलों का रिकॉर्ड ऑनलाइन होगा। इसको लेकर आयुक्त भू-अभिलेख ने सभी जिलों के कलेक्टरों को पत्र भी जारी कर दिए हैं। यह होती है गिरदावरी किसानों को सरकार की योजनाओं से जोड़ने के लिए उनके खेत का रकबा और होने वाली फसल को आधार बनाया जाता है।

# नागरिकों की शिकायतों को त्वरित गति से निराकृत करें

### महापौर श्रीमती मालती राय ने महापौर हेल्प लाईन की समीक्षा करते हुए दिये निर्देश

**भोपाल।** महापौर मालती राय ने निर्देशित किया है कि महापौर हेल्प लाईन सहित अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों का त्वरित गति से निराकरण किया जाये। महापौर राय ने यह निर्देश महापौर हेल्प लाईन की समीक्षा करते हुए दिये। समीक्षा के दौरान महापौर श्रीमती राय ने अनेक शिकायतकर्ताओं से दूरभाष पर चर्चा की और फीडबैक लिया। शिकायतकर्ताओं ने अपनी शिकायतों के त्वरित निदान होने के संबंध में अवगत कराया और महापौर के प्रति आभार भी व्यक्त किया।

महापौर मालती राय ने मंगलवार को स्मार्ट सिटी कार्यालय स्थित कॉल सेंटर में महापौर हेल्प लाईन की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान महापौर श्रीमती राय ने हेल्प लाईन पर प्राप्त शिकायतों एवं उनके निराकरण के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी प्राप्त की। महापौर श्रीमती राय ने सीवेज, स्ट्रीट लाईट, जलकार्य, अतिक्रमण, डॉग स्क्वाड सहित अन्य लंबित शिकायतों के निराकरण के संबंध में संबंधित विभागों के अधिकारियों से दूरभाष पर चर्चा की और महापौर हेल्प लाईन पर लंबित शिकायतों को तत्काल निराकृत करने के निर्देश दिए। महापौर श्रीमती राय ने निर्देशित किया कि महापौर हेल्प लाईन नागरिकों की शिकायतों के त्वरित निराकरण हेतु स्थापित की गई है। इस पर प्राप्त शिकायतों को अधिकतम 24 घण्टे की समय सीमा में निराकृत करें। इस दौरान महापौर श्रीमती राय ने अनेक शिकायतकर्ताओं से भी दूरभाष पर चर्चा की और शिकायतों के निराकरण के संबंध में फीडबैक लिया। नागरिकों ने शिकायतों के त्वरित गति से निराकृत होने की जानकारी दी और शिकायतों के त्वरित निदान पर महापौर एवं नगर निगम के प्रति आभार भी व्यक्त किया।

# हॉरर-कॉमेडी में रश्मिका के साथ रोमांस का तड़का लगाएंगे आयुष्मान

मुंज्या की आपार सफलता के बाद आदित्य सतपोदर और दिनेश विजान एक और धमाका करने वाले हैं। मेकर्स एक और हॉरर कॉमेडी फिल्म बनाने की तैयारी में हैं। इस फिल्म का टाइटल 'वैम्पायर्स ऑफ विजय नगर' दिया गया है।

फिल्म में कथित तौर पर आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की जोड़ी नजर आ सकती है। रिपोर्ट के अनुसार यह फिल्म भी कनेक्टेड होगी और दिनेश विजान की हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का हिस्सा होगी। दिनेश विजान को वैसे भी अब इस फील्ड का मास्टर कहा जा सकता है। उन्होंने साल 2018 में स्त्री से शुरुआत की। इसके

बाद वो भेड़िया और फिर मुंज्या लेकर आए। पिंकविला की एक रिपोर्ट के अनुसार, दिनेश विजान ने आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना को लीड रोल के लिए लॉक कर लिया है। फिल्म की कहानी वैम्पायर्स पर बेस्ड होगी। आयुष्मान खुराना और दिनेश विजन ने इससे पहले बाला में भी साथ काम किया है। फिल्म के प्लॉट पर काफी समय से बात चल रही थी और अब मेकर्स इसे इस साल के अंत तक फ्लोर्स पर ले जाने की तैयारी में हैं।

आपको बता दें कि अभी इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है और जल्द ही इसका प्री-प्रोडक्शन काम शुरू हो जाएगा। इस साल के अंत तक नवंबर में शूटिंग शुरू हो सकती है। आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना पहली बार किसी फिल्म में साथ नजर आएंगे।

# मशहूर एक्ट्रेस ने सौतेले भाई से रचा ली शादी

बहन-भाई का रिश्ता बेहद पवित्र होता है। लेकिन कुछ लोगों के लिए शायद ये मायने ही नहीं रखता है। कभी कोई महिला अपने सौतेले बेटे को पति बना लेती है तो लड़का अपनी सौतेली बहन से भी शादी करने को तैयार हो जाता है। सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की को अपने सौतेले भाई से प्यार हो गया और उसने उसी से ही शादी कर ली।

ये लड़की एक मशहूर एक्ट्रेस है। लड़के का नाम टायो रिक्की तो उसकी सौतेली बहन का नाम स्कारलेट वास है। शादी के बाद इन दोनों ने डांस करते हुए वीडियो शेयर किया है स्कारलेट और टायो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। स्कारलेट वास मशहूर टीवी शो नेबर्स में एक्टिंग कर चुकी

हैं। उन्हें ऑस्ट्रेलिया में उनके किरदार मिष्टी शर्मा के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन पिछले साल ही उन्होंने अपने सौतेले भाई से शादी करने के फैसले से सबको चौंका दिया था। लोग इस बात की कड़ी आलोचना भी कर रहे थे लेकिन स्कारलेट सौतेले भाई से शादी तक ही नहीं रुकीं। उन्होंने एक और चौंकाने वाला फैसला लिया। स्कारलेट ने टीवी की दुनिया को सिर्फ इसलिए अलविदा कह दिया, क्योंकि उन्हें डर्टी वेबसाइट पर अपना वीडियो बनाना था। वे अपने सौतेले भाई (जो अब उनके पति हैं) के साथ ओनली फैंस के लिए वीडियोज बनाती हैं। इसके जरिए वो जमकर नोट छाप रही हैं।

टायो रिक्की ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि हमारे सच्चे प्यार को लगभग 1 साल। इस वीडियो में स्कारलेट और उनका भाई टायो (अब पति-पत्नी) डांस करते हुए नजर आ रहे हैं।

# कॉमेडी प्ले में नजर आएंगी श्वेता तिवारी

टीवी से लेकर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस श्वेता तिवारी इस समय सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। श्वेता तिवारी ने भले ही अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत टीवी से की थी लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में भी उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। श्वेता तिवारी अपने एक्टिंग और डांस स्किल्स, दोनों से फैंस का दिल जीतना जानती हैं। कई भोजपुरी फिल्मों में उनके डांस नंबर्स ने लोगों को अपना दीवाना बना दिया है। इंटरनेट पर छाई हुई हैं श्वेता तिवारी श्वेता तिवारी आए दिन अपनी फिटनेस और खूबसूरती की वजह से चर्चा में बनी रहती हैं, लेकिन इस बार किसी खास वजह से वह इंटरनेट पर छाई हुई हैं। एक्ट्रेस ने अपने फैंस को एक गुड न्यूज दी है, जिससे सुनकर लोग खुशी से झूम उठे हैं। उन्होंने लोगों

को इस बात की जानकारी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए बताई है। आइए आपको बताते हैं कि अपने फैशन का जलवा बिखेरने वाली श्वेता तिवारी ने लोगों को क्या खुशखबरी सुनाई है।

श्वेता तिवारी ने फैंस को दी ये खुशखबरी

श्वेता तिवारी ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है- अपने अपकमिंग हिंदी कॉमेडी प्ले एक मैं और एक दो का ऐलान करते हुए खुशी महसूस हो रही है। लाफ्टर और इमोशन के रोलरकोस्टर के लिए तैयार हो जाइए। मैं अब बाकी कलाकारों से मिलने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती! क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि वे कौन हो सकते हैं? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार श्वेता तिवारी एक नया प्ले करने जा रही है। इस कॉमेडी प्ले का नाम एक मैं और एक दो है।

## नाना पाटेकर ने यौन शोषण के आरोपों को झुठलाया तो भड़की तनुश्री दत्ता

कई बॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुकी एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता उस समय काफी चर्चा में रही थी जब देश में मीटू अभियान चला था। तब कई बॉलीवुड एक्ट्रेस ने अपने साथ हुई गलत घटनाओं के बारे में दुनिया को बताया था। तब ही तनुश्री ने बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर नाना पाटेकर पर संगीन आरोप लगाए थे।

नाना पाटेकर पर एक्ट्रेस ने मीटू अभियान के दौरान यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। तब नाना को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। आज तक भी तनुश्री नाना पर लगाए गए अपने आरोपों पर अडिग हैं। वहीं, अब तनुश्री ने फिर से इस मामले पर बात की है। हाल ही में पहले नाना ने तनुश्री के आरोपों पर एक इंटरव्यू में इसे लेकर कुछ कहा था। नाना पाटेकर के बयान पर अब एक्ट्रेस ने रिएक्ट किया है।

**नाना पाटेकर डरे हुए हैं**

नाना पाटेकर के बयान पर बोलते हुए तनुश्री ने कहा है कि वे डरे हुए हैं। हाल ही में नाना ने एक इंटरव्यू दिया था। वहीं अब तनुश्री ने भी इंटरव्यू दिया है। इस दौरान एक्ट्रेस ने नाना को लेकर कहा, अब, वह डरे हुए हैं और बॉलीवुड में उनका सपोर्ट बेस कम हो गया है। आपको बता दे कि तनुश्री और नाना पाटेकर साथ काम कर चुके हैं। साल 2008 में आई फिल्म हॉर्न ओके प्लीज में दोनों को साथ देखा गया था। भारत में साल 2018 के मीटू इंडिया अभियान के दौरान तनुश्री ने यह खुलासा करके सभी को हैरान कर दिया था कि इस फिल्म के एक स्पेशल गाने की शूटिंग के दौरान एक्टर ने उनके साथ गलत व्यवहार किया था।

# कुर्ता सिलवाते वक्त ध्यान रखें ये बातें

भारतीय परिधानों का अपना एक आकर्षण है। यह दिखने में जितने अच्छे लगते हैं, पहनने में उतने ही आरामदेह होते हैं। फिर चाहे वो साड़ी हो या लहंगा। मगर एथनिक वॉर्डरोब में कुर्ता एक ऐसा परिधान है, जो सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। दरअसल, यह एक आरामदेह पहनावा है, साथ ही विविधता से भरा है। किसी भी समारोह के लिए यह परफेक्ट होता है। सबसे बड़ी बात कि यह सदाबहार है, जो कभी भी फैशन से बाहर नहीं होता। अगर आप अपनी पसंद का कुर्ता सिलवाकर पहनना पसंद करती हैं तो कुछ बातों का ख्याल रखें।

**बाजार** में यूं तो रेडीमेड कपड़ों की कमी नहीं है मगर जब बात स्टाइल और फैशन की हो तो आज भी सिलवाए हुए कपड़े पसंद किए जाते हैं। वैसे भी कुर्ते में तो डिजाइन की कोई कमी नहीं है। मगर कुर्ते की ये सारी खासियतें तभी उभरकर आती हैं जब वो अच्छे से सिला गया हो और उसकी फिटिंग अच्छी हो। हालांकि समय की कमी की वजह से आजकल बहुत सी महिलाएं रेडीमेड कुर्ते ही खरीद लेती हैं। मगर कुछ महिलाओं को रेडीमेड पसंद नहीं आते और वह कपड़ा खरीदकर सिलवाना पसंद करती हैं। लेकिन कुर्ता अच्छे से सिला ना जाए तो उसका पूरा लुक खराब हो सकता है। कुर्ता सिलवाने के लिए एक अच्छा टेलर होना तो जरूरी है ही उसके अलावा भी कुछ बातें हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है।

**थोड़ा ज्यादा कपड़ा लें :** कुर्ते के लिए कपड़ा खरीदते वक्त हमेशा थोड़ा जरूरत से ज्यादा कपड़ा खरीदें। अगर आमतौर पर आप दो मीटर कपड़ा खरीदती हैं तो सवा दो या ढाई मीटर कपड़ा खरीदें। हमें कई बार एहसास नहीं होता है मगर हमारे शरीर का नाप घट-बढ़ जाता है। ऐसे में एक्स्ट्रा फैब्रिक होने से आपको सही फिटिंग मिलती है। इसके अलावा कई बार टेलर के पास जाकर हमें बाजू या कुर्ते का कोई ऐसा डिजाइन पसंद आता है, जिसके लिए हमेशा लिया जाने वाला कपड़ा कम पड़ सकता है, ऐसे में ज्यादा कपड़ा लेना हमेशा सही फैसला होता है।

**कपड़ा धो कर सिलने दें :** कई बार आपके साथ हुआ होगा कि कुर्ता सिलकर आने के बाद तो सही फिटिंग रहती है, मगर पहली बार धोने के बाद वह तंग हो जाता है या कई हिस्सों से लटक जाता है। ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि कुछ फैब्रिक ऐसे होते हैं जो धोने के बाद सिकुड़ जाते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो फैल जाते हैं। ऐसी परेशानी से बचने के लिए बेहतर ये है कि आप टेलर को कुर्ता सिलने के लिए दें उससे पहले कपड़े को रात भर पानी में भिगोकर रखें फिर छांव में सुखा लें।

**मार्जिन रखने को कहें :** वजन ऊपर-नीचे होना एक आम समस्या है, मगर इस समस्या के चलते अक्सर हमें अपने कई पसंदीदा कपड़ों का त्याग करना पड़ता है। ढीले हुए कपड़े तो फिर भी टाइट करवाए जा सकते हैं, मगर टाइट हुए कपड़ों को अक्सर हमें किसी को देना ही पड़ जाता है। ऐसा ना हो इसके लिए अपने टेलर को हमेशा कुर्तों में मार्जिन रखने को कहें, जिससे कसे होने पर इस मार्जिन को खोलकर ढीला किया जा सके। रेडीमेड कुर्तों में आपको कभी भी मार्जिन नहीं मिलेगा, मगर सिलवाए गए कुर्तों में आप अपने हिसाब से मार्जिन रख सकती हैं।

**इंटरलॉकिंग जरूर करवाएं :** जब भी कुर्ता सिलवाएं तो टेलर से अंदर की तरफ इंटरलॉकिंग करने को जरूर कहें। कई टेलर सिर्फ सिलाई करके दे देते हैं, मगर इंटरलॉकिंग करने से कुर्ते को अच्छी सफाई मिलती है और लुक भी अच्छा आता है। इंटरलॉकिंग करने से अंदर से धागे खिंचने का या सिलाई खुलने का भी डर नहीं रहता है।

### बचे कपड़े के टुकड़े रख लें

कुर्ता सिलवाते वक्त कपड़ा बचना काफी आम है, ज्यादातर टेलर इसे या तो फेंक देते हैं या अपने पास रख लेते हैं। अपने टेलर से वो कपड़ा मांग लें, इससे आप अपने दूसरे कपड़ों पर पैचवर्क, पाइपिंग या लटकन बनवा के लगवा सकती हैं। या फिर हो सकता है कि कभी आपके कुर्ते में किसी वजह से छोटा सा कट पड़ जाए। ऐसे में यही बचा हुआ कपड़ा देकर कपड़ा रफू करवाया जा सकता है।

### हर बार नाप दें

जब भी कुर्ता सिलवाने जाएं तो खुद का नाप दें। परफेक्ट फिटिंग के लिए ये बहुत जरूरी है। बहुत सी लेडीज टेलर के पास अपने पुराने नाप से या अपना कोई पुराना कुर्ता देकर उसी के हिसाब से नया कुर्ता सिलवा सकती हैं। ऐसा करने से कई बार आपके कुर्ते की फिटिंग में अंतर हो सकता है। अच्छी फिटिंग देने के लिए कुर्ते का नाप देना बहुत जरूरी है।

## काम की बातें

### बिंदी न बन जाए एलर्जी की वजह

**बात** जब सजने संवरने की आती है तो बिंदी के बिना सब अधूरा लगता है। छोटी और बड़ी दोनों तरह की बिंदी माथे पर खूब जंचती हैं। मगर कुछ महिलाओं को बिंदी की वजह से एलर्जी भी हो सकती है। दरअसल बिंदी में इस्तेमाल की जाने वाली ग्लू त्वचा कुछ महिलाओं को नहीं सुहाती, जो उनमें एलर्जी का कारण बन सकती है। यह दिक्कत गर्मियों में और ज्यादा बढ़ जाती है। कुछ महिलाएं हर समय चेहरे पर बिंदी लगाए रखती हैं, जिससे त्वचा पर खुजली और लाल निशान हो सकते हैं। बिंदी से होने वाली एलर्जी को चिकित्सा की भाषा में बिंदी डर्मेटाइटिस कहा जाता है। बिंदी में आमतौर पर पैरा टर्शरी ब्यूटाईल प्लेनोल का इस्तेमाल होता है, जो संवेदनशील त्वचा के लिए नुकसानदायक है। लम्बे समय तक इसका इस्तेमाल करते रहने से त्वचा को नुकसान हो सकता है। महिलाएं अक्सर शुरुआती लक्षणों पर ध्यान नहीं देतीं और बिंदी लगाना जारी रखती हैं। अगर आपको बिंदी से होने वाली एलर्जी के लक्षण दिखाई दें तो तुरंत बिंदी का इस्तेमाल बंद कर दें। हालांकि भारतीय समाज में ऐसा संभव नहीं। इसलिए बिंदी के स्थान पर अन्य उत्पाद इस्तेमाल करें।

### लॉकडाउन में नहीं खलेगी पार्लर की कमी

**लॉकडाउन** में पार्लर जाना तो असंभव सा हो गया है तो क्यों न ऐसे में घर पर ही कुछ तरीके आजमाए जाएं। बालों की सुरक्षा के लिए सिर की मालिश जरूर करें। बालों की लंबाई नहीं बढ़ रही है या ट्रिमिंग की जरूरत महसूस हो रही है तो ट्रिमिंग भी कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए यूट्यूब की मदद ले सकती हैं या फिर आजकल कई विशेषज्ञ सोशल साइट्स पर ट्यूटोरियल्स दे रहे हैं। इसकी मदद लें। इसी तरह चेहरे की देखभाल के लिए महीने में एकाध बार घर पर फेशियल कर सकती हैं। अगर संयुक्त परिवार है और एक से ज्यादा महिला सदस्य हैं तो सब मिलकर एक-दूसरे का फेशियल कर सकती हैं। इसके लिए बस कोई मसाज क्रीम लें और फेसपैक शहद, केला, पपीता या टमाटर से घर में तैयार कर सकती हैं। 20-25 मिनट चेहरे की मालिश करें और फिर फेस पैक लगा दें। सूखने पर धो लें।

**यह भी जानें** दूध सेहत के लिए सिर्फ शक्तिवर्द्धक ही नहीं होता, बल्कि त्वचा के लिए भी काफी फायदेमंद होता है, तो क्यों न इसका इस्तेमाल खूबसूरती बढ़ाने के लिए भी किया जाए

# दूध से तैयार फेसपैक से दूध सा चमक उठेगा चेहरा

दूध हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें भरपूर पोषण होता है। मगर शायद ही आपको पता हो कि यह खूबसूरती निखारने के मामले में भी बेहद उपयोगी है। चेहरे को निखारने के लिए आप मिल्क पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटी भी अपनी त्वचा की खूबसूरती बढ़ाने के लिए दूध से तैयार फेस पैक लगाते हैं। आइए जानते हैं मिल्क पाउडर से आप अपनी त्वचा को कैसे चमकदार बना सकती हैं।

**हर** महिला चेहरे को खूबसूरत बनाना चाहती है। वह इसका खास ख्याल भी रखती है। इसके लिए ब्यूटी पार्लर में जाकर तमाम सौंदर्य उत्पादों का प्रयोग करने में पीछे नहीं रहती मगर खूबसूरती का एक उपाय घर पर भी मौजूद होता है। वह भी बहुत आसान, और यह उपाय है दूध और दूध से तैयार फेसपैक। इस वक्त जबकि आपका ब्यूटी पार्लर जाना भी संभव नहीं है तो इन तरीकों को आजमा कर देखें।

**मिल्क पाउडर, बेसन और संतरे का मास्क :** हम अपनी त्वचा की देखभाल के लिए महंगी क्रीम, स्किन सप्लीमेंट्स पर पैसे खर्च करते हैं, ताकि यह सुरक्षित रहे। त्वचा की देखभाल में मिल्क पाउडर बेहद कारगर साबित हो सकता है। मिल्क पाउडर, बेसन और संतरे के रस का मिश्रण त्वचा के लिए बहुत अच्छा है। इन तीनों को बराबर मात्रा में मिलाकर फेस पैक बनाएं और पेस्ट को चेहरे और गर्दन पर लगा लें। इसे सूखने दें और 15 मिनट बाद धो लें। आपको तुरंत फर्क नजर आयेगा।

**मिल्क पाउडर, दही और नींबू का मास्क :** दही, नींबू और मिल्क पाउडर को मिलाकर लगाने से त्वचा पर मौजूद डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन की समस्या से छुटकारा मिलेगा। साथ ही इससे प्राकृतिक चमक बढ़ती है। आपको बस इन तीनों चीजों को मिलाकर चेहरे पर 20 मिनट के लिए लगाना है और फिर ठंडे पानी से धो लेना है।

### मिल्क पाउडर और मुल्तानी मिट्टी

तैलीय त्वचा धूल और हवा में मौजूद कई हानिकारक कणों को सोख लेती है। इससे मुंहासे होने लगते हैं। यह त्वचा की पूरी चमक खींचकर इसे बेजान और रूखा भी बना देते हैं। ऐसे में मिल्क पाउडर और मुल्तानी मिट्टी के मास्क से आपको अपनी तैलीय त्वचा में दोबारा जान डालने में मदद मिलेगी। आप बस इन्हें पानी के साथ मिलाकर चेहरे पर लगा लें। यह त्वचा में मौजूद गंदगी को खींच लेंगे। सूखने पर इसे धो लें। हफ्ते में कम से कम दो बार इसे चेहरे पर लगाएं और फर्क देखें।

# क्लीन सिटी के साथ ग्रीन सिटी में इंदौर नम्बर वन बनेगा-डॉ. मोहन यादव

**इंदौर।** प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संकल्प एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव तथा केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने आज इंदौर स्थित बीएसएफ रेंज क्षेत्र में वृहद स्तरीय वृक्षारोपण कार्यक्रम में सहभागिता करते हुए अपनी माताजी की याद में वृक्षारोपण किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपनी माताजी स्व. लीलाबाई श्री पूनमचंद जी यादव की स्मृति में बड का वृक्ष लगाया। केन्द्रीय मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव ने अपनी माताजी श्रीमती संतरा यादव की याद में आम का वृक्ष, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने अपनी माताजी अयोध्या देवी विजयवर्गीय की याद में आम का वृक्ष लगाया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा आदिकाल से इंदौर और उज्जैन का पर्यावरण के महत्व में विशेष संबंध रहा है। मां क्षिप्रा का उद्गम इंदौर से है। 7 नदियों के उद्गम का स्थल इन्दौर ही है। देश एवं दुनिया में इंदौर की विशेष पहचान है। क्लीन सिटी के साथ ग्रीन सिटी में इंदौर अवश्य नम्बर वन बनेगा। आज बीएसएफ रैंज में बडी संख्या में माताएं अपने बच्चों के साथ उपस्थित हुई और वृक्षारोपण किया। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर देश में एक पेड़ मां के नाम अभियान के माध्यम से वृक्षारोपण किया जा रहा है। उन्होंने कहा केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री के प्रयास से मध्य प्रदेश को चीते मिले, जो प्रदेश के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा भारतीय समाज सदैव से प्रकृति पूजक रहा है। भारत की वैदिक परंपराओं में कहा गया है कि 10 कुओं के समान एक सरोवर, 10 सरोवर के समान एक तालाब, 10 तालाब के समान एक पुत्र और 10 पुत्रों के समान एक वृक्ष होता है। ऐसी हमारी वैदिक मान्यता होकर वृक्ष की महत्ता हमारी परम्परा में है। भारतीय समाज सदैव से प्रकृति पूजक रहा है। उन्होंने कहा इंदौर क्लीन सिटी के साथ ग्रीन सिटी बनेगा, इसी संकल्प के साथ पूरा इंदौर इस अभियान से जुड़ा है।

केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव ने कहा प्रधानमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ किया। पूरे देश में 140 करोड़ वृक्ष लगाने का महा अभियान चल रहा है। उन्होंने कहा इस वर्ष गर्मी का प्रचंड रूप 45 से 50 डिग्री तापमान के रूप में देखने को मिला। उन्होंने कहा पूरी दुनिया में विकास और परियोजनाओं को पूरा करने के लिए मनुष्य ने कांक्रिट के शहर तो बसा दिए लेकिन धरती की हरियाली को उजाड़ दिया। मनुष्य कितनी भी तरक्की कर ले लेकिन भोजन, पानी, दवाओं का अंतिम एलिमेंट सहित कई जरूरतें प्रकृति उपहार में देती है लेकिन हम प्रकृति को इसके बदले में क्या लौटाते है। एक मां ने हमें जन्म दिया तथा एक धरती मां हमें जीवन जीने के साधन प्रदान करती है। जीवन देने वाली मां को नमन करने और प्रकृति मां के प्रति सम्मान के प्रति हरी भरी धरती देने के संकल्प को पूरा करना हमारा कर्तव्य है। धरती केवल इंसान के लिए नहीं समस्त जीव मात्र के लिए है, इसलिए इस अभियान के माध्यम से देश में एक वृक्ष माँ के नाम अभियान के तहत प्रत्येक देशवासी से वृक्षारोपण का आह्वान किया गया है। वृक्षारोपण की पहल में म.प्र. का प्रयास सराहनीय है। इंदौर वासियों का क्लीन इंदौर के साथ ग्रीन इंदौर बनाने का अभियान प्रशंसनीय है। केन्द्रीय मंत्री श्री यादव एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का सम्मान पगडी, दुपट्टा एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर किया गया। कार्यक्रम को नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने संबोधित करते हुए कहा इंदौर के ग्रीन कवरेज को बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा 51 लाख वृक्षों के रोपण के साथ इनके संरक्षण हेतु भी।

## मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री के साथ देवी अहिल्या माता की प्रतिमा पर रुद्राक्ष के पौधे भी रोपे

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संकल्प एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेने हेतु मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव तथा केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव आज इंदौर पहुंचे। इंदौर पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले देवी अहिल्या माता की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने इस अवसर पर रुद्राक्ष के पौधों का रोपण भी किया। इस अवसर पर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय, जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव, विधायक श्री गोलू शुक्ला, श्री गौरव रणदिवे, श्री चिंटू वर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि विशेष रूप से मौजूद थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि यह हमारे लिए बड़ी ही खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण संरक्षण के लिए एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत पूरे प्रदेश में साढ़े 5 करोड़ पौधों का रोपण किया जा रहा है। यह गर्व का विषय है कि इंदौर शहर और पूरे जिले में 51 लाख पौधे लगाए जाने का कार्य शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वृक्षारोपण अभियान एक जन अभियान का रूप ले रहा है। इसमें समाज के हर वर्ग की सक्रिय सहभागिता सामने आ रही है।

# एक पेड़ मां के नाम अभियान को लेकर विधानसभावार बैठक संपन्न

**इन्दौर।** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर प्रकृति के संरक्षण हेतु भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे देश में एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया जा रहा है। इस ही क्रम में जावरा कंपाउंड स्थित भाजपा कार्यालय पर विधानसभावार बैठके आयोजित की गई नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय एवं नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे ने बैठक को संबोधित किया। इस अवसर पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि 51 लाख वृक्षारोपण का लक्ष्य शुरुआत में काफी बड़ा लग रहा था, लेकिन इंदौरवासियों के उत्साह और उनकी सक्रियता ने इसको छोटा कर दिया है। 51 लाख वृक्षारोपण के लिए अभी तक लगभग 48 लाख गड्डे किए जा चुके हैं। 70 मशीनों की मदद से डेढ़ लाख गड्ढे रोजाना खोदे जा रहे हैं। शहर में 19 लाख वृक्ष लगाए जाएंगे। इसमें से 5 लाख वृक्ष शहर के बगीचों में लगाए जाएंगे। आईडीए शहर में 3 लाख पेड़ लगाएगा। वन विभाग द्वारा 20 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। 7 जुलाई रविवार को 11 बजे बिजासन टेकरी स्थित बीएसएफ रेंज पर मातृवन की स्थापना की गई। मातृवन में करीब 15 हजार मातृशक्तियों के द्वारा 1 लाख वृक्षों का रोपण किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्रजी यादव एवं मुख्यमंत्री मोहनजी यादव मातृवन में उपस्थित रहकर मातृशक्ति का उत्साहवर्धन किया। नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे ने कहा कि सभी को अभियान में अपना सहयोग देकर बढ़-चढ़कर सहभागिता करना है एवं पेड़ लगाने के साथ ही पेड़ों का संरक्षण करना भी हमारी जवाबदारी है।

## एमपी प्री स्टेट शूटिंग प्रतियोगिता में राज्य के 700 से अधिक निशानेबाज शामिल

**इन्दौर।** देश सेवा की चाह लिए अपने बुलंद हौसलों के साथ इंदौर में चल रहे शूटिंग कॉपिटिशन में खिलाड़ियों द्वारा हर दिन बेहतरीन प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल, मध्यप्रदेश राज्य राइफल एसोसिएशन के माध्यम से सीमा सुरक्षा बल रेवती रेंज इंदौर में 6 दिवसीय फर्स्ट एमपी प्री स्टेट शूटिंग प्रतियोगिता 2024 का आयोजन चल रहा है। संगठन के सेक्रेटरी राकेश गुप्ता और वाइस प्रेसिडेंट डीके शुक्ला ने बताया कि प्रदेश के लगभग 30 से 35 जिलों के 700 से अधिक 12 से 40 वर्ष तक के निशानेबाजों के द्वारा बंदूक का ट्रिगर दबाकर निशाना साधा जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज, बीएसएफ में सहायक समादेष्ठ और कॉमनवेल्थ के गोल्ड मेडलिस्ट नरेश कुमार ने बताया कि बीएसएफ रेवती रेंज इंदौर में स्थित स्व. मोहिंदरलाल एयर शूटिंग गैलरी में 3 से 8 जुलाई तक यह प्रतियोगिता चल रही है। जहां बीएसएफ द्वारा निशानेबाजों के प्रोत्साहन हेतु हर तरह की जरूरते मुहैया कराई जा रही है। वहीं रविवार को हुई शूटिंग के दौरान इस खेल के प्रति निशानेबाजों में काफी उत्साह दिखाई दिया। आयोजन में इस खेल से जुड़े वरिष्ठजनों के साथ ही युवा उद्योगपति शंकर ठाकुर और समाजसेवी विजय चौहान सहित कई लोग मौके पर मौजूद रहे और निशानेबाजों का हौसला बढ़ाया। आयोजकों के मुताबिक मध्य प्रदेश स्टेट राइफल एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश मेंदोला के मार्गदर्शन में प्रदेश के शूटरों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए विभिन्न तरह के टूर्नामेंट लगातार कराए जा रहे हैं, वहीं शूटिंग जैसे खेल के जरिए नई प्रतिभाओं को आगे लाने के प्रयास लगातार जारी है।

प्रकाशक, मुद्रक एवं स्वामी जयश्री जैन द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स 13, प्रेस कॉम्प्लेक्स ए.बी. रोड इंदौर से मुद्रित एवं 22, प्रेस काम्पलेक्स, प्रेस हाऊस, ए.बी. रोड इंदौर 452008 से प्रकाशित। प्रधान संपादक- डॉ. राजेश जैन, मो. 9425322301 ( डाक पंजीयन MP/IDC/1462/2016-2019 )